(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY

(Respondent No. 2)

in

Original Application No. 349/2024

Yashpal Singh

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-5
3.	**Annexure No. 1** (Copy of the MoEF&CC notification dated 06.01.2020)	6-9
4.	**Annexure No. 2** (Copy of the notification dated 13.12.2007)	10-11

Dated: 30th November 2024

Dr. Aman Rab
Advocate
(Counsel for Respondent No. 2)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY

(Respondent No. 2)

in

Original Application No. 349/2024

Yashpal Singh

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Affidavit of Shri Amulya Ratan Sinha, aged about 68 years, S/o Dr. Brij Kishor Sinha presently posted as Chairman, SEIAA, Paryavaran Bhawan, IT Park, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as the Chairman, State Environment Impact Assessment Authority Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit. It is pertinent to bring it on record that the authority has been reconstituted by Government of India vide notification no. CG-DL-E-06102022-239372 dated 04.10.2022 and the deponent is submitting the reply on the basis of records available in the office of SEIAA.

NOTARIAL

NOTARIAL

NOTARY * Km. Urmila Bhatia * Advocate * Reg.No. [illegible] Dehradun. * STATE OF UTTARAKHAND *

NOTARY * Km. Urmila Bhatia * Advocate * Reg.No. [illegible] Dehradun. * STATE OF UTTARAKHAND *

PARA WISE REPLY: 385

2) That the contents of Paragraph No. 1 do not call for any reply from the answering respondent.

3) That the contents of paragraph no. 2 (a) to 2 (p) are admitted only insofar as they are matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied. However, it is pertinent to mention that M/s Balaji Stone Crusher, i.e., respondent no. 6 was granted environmental clearance by the answering respondent on 01.02.2024, which is already on record as Annexure 12 at page no. 203 to the paper book filed by the applicant/petitioner.

4) It is pertinent to mention that as per Table G-3 : Final List of Orange Category of Industrial Sectors of CPCB notification dated 07.03.2016, stone crushers were included in the orange category at serial no. 64. The relevant portion is reproduced hereunder: -

Final Sl. No.	Orgnl S.No	Orgnl S.No	W1	W2	W	A1	A2	A	H	W+A+H	Revised category	Remarks
64.	73	Stone crushers	-	-	-	20	-	20	-	50	R-O	Mainly air polluting. Air pollution score is normalized to 100.

5) That as a result Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) Doon Valley Notification dated 06.01.2020 amended the 1989 doon valley notification and the re-classification of industries in to red, orange, green and white was made applicable to Doon Vally Area and there is provision that industries falling in orange category in which stone crusher is also included will have to obtain Environmental Clearance from SEIAA. In this connection a copy of the MoEF&CC notification dated 06.01.2020 is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

6) That vide S.O. 2125(E) dated 13.12.2007 the procedure w.r.t Environmental Clearance (EC) mechanism for the orange category of industries in the Doon Valley was laid down. As per point number 2 of the said notification, all those projects which fall under the Orange Category as per CPCB shall be considered by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for the grant of E.C. In this connection a copy of notification dated 13.12.2007 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

7) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.

Deponent

Verification: -

I, Amulya Ratan Sinha, do hereby solemnly affirm and verify on oath that the contents of the above affidavit in paragraph nos. 1(p), 2, 5(p) and 7 are true to my personal knowledge and those in paragraph nos. 1(p), 3, 4, 5(p) and 6 are based on the perusal of records. Nothing material has been concealed and no part of it is untrue. So help me God.

Deponent

I, Deepak Dobhal, Advocate, do hereby identify Amulya Ratan Sinha from his Aadhar Card No. 5029 0760 5399 who has produced the records of the case before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

Deepak Dobhal
Advocate
UK 131/2024

Solemnly affirmed before me on this 29 day of November, 2024 at Dehradun at about 1.30 ~~AM~~/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

Notary

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-03/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

affidavit is sworn before me by
.... Amulya Ratan Sinha ....
is identified by Deepak Dobhal Adv.
Dehradun on .....
29/11/2024

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

Annexure No. 1 (6)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215285
CG-DL-E-10012020-215285

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
No. 86] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. 94(अ).— अधिसूचना संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) को, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) में दून घाटी में, उत्तर में मसूरी रिज़ से घिरा, उत्तर-पूर्व में हिमालयी पर्वतश्रेणी, दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक श्रेणियों द्वारा, दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी और उत्तर-पश्चिम में यमुना नदी में उद्योगों, खनन कार्यों और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों पर, क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा दिया था;

और, उक्त अधिसूचना के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश अधिसूचना संख्या का.आ. 943 (अ), तारीख 4 जुलाई, 2005 और का.आ. 2125 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा जारी किए गए हैं;

और, इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पत्र सं. बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को उद्योगों के वर्गीकरण पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

और, उत्तराखंड सरकार ने पत्र सं. 122/डी-3-19-13(04)/2018, तारीख 10 अप्रैल, 2019 को उक्त अधिसूचना में संशोधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया;

NOTARY Km. Urmila Bhatt Advocate Reg.No.-09/05/02 Dehra Dun. STATE OF UTTARAKHAND

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के अनुरोध की जांच की है;

और, उपर्युक्त संशोधनों और दिशा-निर्देशों को समेकित करने और उक्त निर्देशों और संशोधनों के आधार पर शर्तों का सामंजस्य करने की भी आवश्यकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), के साथ धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं और उपरोक्त मानदंड में मिल कर बनने वाली दून घाटी में आने वाले क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करें, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और उपाबंध, के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (i) **औद्योगिक इकाइयों के अवस्थान/स्थल –** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पत्र सं. बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को धारा 18 (1) (बी) के तहत जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लाल/नारंगी/हरा/सफ़ेद श्रेणियों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के सांमजस्य के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और सीपीसीबी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ii) **खनन-** किसी भी खनन क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी अभिप्राप्त करनी होगी।

(iii) **पर्यटन-** पर्यटन विकास योजना (टीडीपी) के अनुसार, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iv) **चराई-** राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना के अनुसार और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(v) **भूमि उपयोग-** संपूर्ण क्षेत्र के विकास और भूमि उपयोग योजना के महायोजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

टिप्पण:

(क) दून घाटी में उद्योगों की लाल प्रवर्गों की अनुमति नहीं होगी;

(ख) दून घाटी में ईंधन जलाने वाले उद्योगों की कुल संख्या को सभी स्रोतों से सल्फर डाइऑक्साइड के 8 टन प्रति दिन तक सीमित किया जाएगा। (यह 1% सल्फर के साथ प्रति दिन 400 टन कोयले के समान है।);

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों के स्थल निर्धारित मानदंड पर और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ होगी;

(घ) विद्यमान नारंगी प्रवर्ग के उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल प्रवर्गों में हैं, को जारी रखा जाएगा, तथापि, किसी विस्तार की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।"।

[फा. सं. 25/6/2012-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No 01/01/02 Distt. Distt. STATE OF UTTARAKHAND

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 94(E).—WHEREAS, *vide* notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) the erstwhile Ministry of Environment and Forests imposed restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West in erstwhile Uttar Pradesh (now Uttarakhand), keeping in view the environmental impact in the region;

AND WHEREAS, in respect of the said notification certain directions have been issued *vide* notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005 and S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007;

AND WHEREAS, in the meantime the Central Pollution Control Board (CPCB) has also issued directions on the categorisation of industries *vide* letter No. B-29012/ ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016;

AND WHEREAS, the Government of Uttarakhand *vide* letter No. 122/D-3-19-13(04)/2018, dated the 10th April, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment in the said notification;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Uttarakhand;

AND WHEREAS, there is a need to consolidate the amendments and the directions as above and also to harmonise the conditions based on the said directions and amendments;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and impose following conditions in respect of the activities falling the Doon Valley comprising of the above criteria, namely: -

In the said notification, for clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and ANNEXURE, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Location/siting of industrial units** – It has to be as per modified directions issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) *vide* letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016 under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under red/orange/green/white categories and as may be amended from time to time by the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) **Mining** – Approval of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change must be obtained before starting any mining activity.

(iii) **Tourism** – It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Km. Urmila Gupta
Advocate
Reg.No-
Dehra Dun.

(iv) **Grazing** – As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(v) **Land Use** – As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Note:

(a) Red categories of industries shall not be permitted in Doon Valley;

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Doon Valley shall be limited by 8 tonnes per day of Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 % Sulphur);

(c) Siting of Industrial areas shall be based on the prescribed criterion and with prior approval of Competent Authority;

(d) Existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed.".

[F. No. 25/6/2012-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 102 (E), dated the 1st February,1989.

NOTARY * STATE OF UTTARAKHAND * Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.-[illegible]/02 Dehra Dun.

Attested Photo Copy
Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY,Dehradun

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.10 11:23:38 +05'30'

Annexure No. 2

(10)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929

No. 1539] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2125(अ).—जबकि, पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के तहत दून घाटी, उत्तराखण्ड में उन गतिविधियों जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव के परीक्षण के लिए अनुमति दे दी है, को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 1 फरवरी, 1989 के सं. का.आ. 102(अ) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना में उद्योगों को तीन श्रेणियों अर्थात् ग्रीन, ओरेंज और रेड में वर्गीकृत किया गया है और दून घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं;

और, जबकि, ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का मूल्यांकन राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना तथा उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने से पहले संबंधित प्रस्ताव को केन्द्र सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाना अपेक्षित है;

और, जबकि, यह परिकल्पना की गई थी कि ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रस्तावों के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि दिनांक 4 जुलाई, 2005 के का.आ. 943(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय अपनाई जाती है;

और, जबकि, दिनांक 27 जनवरी, 1994 के का.आ. 60(अ) के तहत जारी उक्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1533(अ) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित हुआ माना जाएगा;

अतः, अब, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, यह निर्देश दिया जाता है कि दून घाटी, उत्तराखंड में विकास कार्यों से संबंधित सभी प्रस्तावों की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए जांच की जाएगी :–

(i) ऐसी सभी परियोजनाएं जो 14 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1533(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत अनुसूची में शामिल की गई हैं, के लिए उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी ।

(ii) ऐसी सभी परियोजनाएं जो उक्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, और ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आती हैं उन पर राज्य स्तर के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

(iii) उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन होने तक, प्रस्तावों की जांच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, उन्हें मूल्यांकन समिति के पास भेजे बिना, केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी ।

[सं. जे-11013/25/2005-आई ए-II (I)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the, 13th December, 2007

S.O. 2125 (E).—Whereas, a notification under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection)

Rules, 1986, imposing restrictions on various activities in Doon Valley Uttarakhand, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts, was issued *vide* No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989;

And, whereas, the said notification classified industries into three categories; namely, green, orange and red and also prescribed guidelines for permitting and restricting industrial units in Doon Valley Area;

And, whereas, industries falling in the orange category are required to be assessed by State Pollution Control Board and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before granting 'No Objection Certificate';

And, whereas, it was envisaged that the proposals covered under orange category shall follow the same procedure as is being followed for the environment clearance of industry sector projects under Environment Impact Assessment Notification, 1994, issued *vide* S.O. 943(E) dated the 4th July, 2005;

And, whereas, the said Environment Impact Assessment notification issued *vide* S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 has been superseded by the notification *vide* number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it is hereby directed that all proposals, relating to development in Doon Valley will be examined as per the following procedure :—

(i) All those projects which are covered in the schedule under the Environment Impact Assessment notification issued *vide* number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 will follow the procedure laid down in that notification.

(ii) All those projects which are not covered under the EIA notification but which fall under the orange category shall be considered by the State level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Till such time as the State level Impact Assessment Authority is constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board.

[No. J-11013/25/2005-IA-II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

NOTARY Km. Urmila Bhatia Advocate Regd. No. 2002 Dehra Dun STATE OF UTTARAKHAND

Attested Photo Copy Km. URMILA BHATIA Advocate & NOTARY, Dehradun

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.